जनसत्ता

घाटी में आतंकी

जम्मू-कश्मीर में साढ़े चार सौ आतंकियों के सक्रिय होने की खबर चौंकाने वाली है। पिछले कुछ समय में सेना ने आतंकियों के खिलाफ जिस तरह से बड़े अभियान चलाए, उससे लग रहा था कि अब आतंकियों का सफाया हो रहा है और आने वाले वक्त में घाटी आतंकियों से मुक्त होगी। लेकिन अब सेना ने ही बताया है कि सबसे ज्यादा आतंकवादी पीर पंजाल के उत्तरी इलाके में सक्रिय हैं। सेना का यह खुलासा बताता है कि आतंकियों का नेटवर्क पूरे राज्य में खासतौर से कश्मीर घाटी के जिलों में फैल चुका है और इसका सफाया अभी भी सुरक्षा बलों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। आए दिन की आतंकी घटनाएं और हमले भी इसकी पुष्टि करते हैं कि राज्य में आतंकी सक्रिय हैं और अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि रोजाना आतंकियों को ढेर किए जाने की खबरें भी आती हैं, लेकिन समस्या यह है कि जितने आतंकी ढेर होते हैं, उससे कहीं ज्यादा पैदा हो जाते हैं। जाहिर है, आतंकी गुट स्थानीय युवाओं को अपने संगठन में भर्ती कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण आतंकियों की गांव-गांव तक में पैठ होना है। इन आतंकी संगठनों का स्थानीय लोगों के बीच ऐसा खौफ है कि जो नौजवान आतंकी गुट में शामिल होने से इनकार करता है, उसकी फिर खैर नहीं।

सेना पिछले तीन दशक से घाटी में आतंकवाद से जूझ रही है। पड़ोसी देश पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ का सिलसिला थमा नहीं है। मौका पाते ही पाकिस्तान आतंकियों को भारत की सीमा में घुसा देता है। सीमापार आतंकवाद पाकिस्तान का भारत के खिलाफ छद्म युद्ध ही है। हालांकि जब नियंत्रण रेखा पर सख्ती ज्यादा होती है और घुसपैठ मुश्किल हो जाती है तो आतंकी हथियारों के साथ नेपाल के रास्ते कश्मीर घाटी पहुंचते हैं। घाटी में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिज्बुल मुजाहिदीन, अल बदर सहित कई छोटे-बड़े संगठन सक्रिय हैं। इन संगठनों के मुख्यालय पाकिस्तान में हैं और इनकी कमान सेना और आइएसआइ के हाथ में रहती है। ये आतंकी संगठन बड़े हमलों को अंजाम देने के लिए भाड़े के आतंकियों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सेना के लिए सबसे बड़ी परेशानी और चिंता की बात यह है कि स्थानीय स्तर पर आतंकियों की भर्ती को कैसे रोका जाए। पिछले साल स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए और विदेशी आतंकियों का अनुपात साठ-चालीस का था। स्थानीय नौजवानों का आतंकवादी संगठनों में भर्ती होना आतंकवाद से निपटने के सरकार के प्रयासों के लिए बड़े झटके से कम नहीं है।

पिछले साल जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया था और दो सौ बासठ आतंकवादियों का सफाया किया था। इनमें लश्कर, जैश और हिजबुल के शीर्ष कमांडर भी थे। इसके बावजूद अगर आतंकियों की संख्या बढ़ रही है तो स्पष्ट है कि कश्मीर घाटी में पाक समर्थित आतंकवाद को पनाह मिल रही है और इसे रोक पाने में राज्य और केंद्र सरकार की नीतियां नाकाम साबित हो रही हैं। संसद में पेश की गई गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि पाक अधिकृत कश्मीर में आइएसआइ की मदद से सोलह आतंकी शिविर चल रहे हैं। सेना एक बार पाक अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर चुकी है और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे चुकी है। लेकिन अब फिर से वहां सोलह आतंकी शिविर चल रहे हैं। सवाल है कि सरकार क्यों चुप बैठी है? सेना को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कड़ा कदम उठाना चाहिए।

जल संकट और चुनौतियां

अखिलेश आर्येंदु

भारत में पानी की किल्लत पिछले दस-पंद्रह सालों में ज्यादा बढ़ी है। इसका कारण सरकार की गलत नीतियां हैं। इन नीतियों का ही परिणाम रहा है कि राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में जल-स्तर दस से पंद्रह फीट तक नीचे चला गया है। इन इलाकों में बोतलबंद पानी का कारोबार बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही कर रही हैं, शीतलपेय बनाने के विशालकाय कारखाने चल रहे हैं।

पानी की बढ़ती किल्लत को लेकर नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ हाइड्रोलॉजी ने एक बहुत दिलचस्प अध्ययन किया है। इसके मुताबिक भारत में विकास की रफ्तार बढ़ने के साथ पानी का संकट बढ़ेगा और पानी को लेकर अनेक प्रदेशों में मारा-मारी मच सकती है। यहां एक बात पर गौर करना होगा कि जीडीपी की दर बढ़ रही है, इससे लोगों की आय में इजाफा हो रहा है और जीवन-शैली में तेजी से बदलाव आ रहा है। जाहिर है, आधुनिक जीवन-शैली प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन पर ही आधारित है। पानी की खपत इसी वजह से पिछले तीस-चालीस साल में तेजी से बढ़ी है। अभी पानी की मांग प्रति व्यक्ति सौ से एक सौ दस लीटर के बीच है, जो 2025 तक बढ़ कर एक सौ पच्चीस लीटर या इससे अधिक हो सकती है। तब तक भारत की आबादी एक अरब अड़तीस करोड़ हो जाएगी और पानी की मांग सात हजार नौ सौ करोड़ लीटर हो जाएगी। लेकिन पानी की उपलब्धता इसकी आधी होगी। राष्ट्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार 1997 में जल की उपलब्धता पांच सौ पचहत्तर क्यूबिक किमी थी (एक क्यूबिक किमी का मतलब 100 अरब लीटर), लेकिन अब यह लगभग पांच सौ क्यूबिक किमी है, जबकि मांग 800 क्यूबिक किमी के लगभग है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उपलब्धता की तुलना में मांग कितनी ज्यादा है।

भूगर्भ विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों पर नजर रखने वाली संस्थाओं के अनुसार भारत के पंद्रह फीसद भूजल स्रोत सूख गए हैं। सबसे ज्यादा कुएं, पंपिंग सैट, ट्यूबवेल भारत में हैं। आंकड़े के मुताबिक जमीन से जल खींचने वाले यंत्रों की संख्या बीस लाख से अधिक है। ऐसे में विश्व बैंक के इस आकलन पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगले बीस सालों में भूजल के साठ फीसद स्रोत खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। भारत के लिए यह स्थिति इसलिए दयनीय बन सकती है कि जल की हमारी सत्तर फीसद मांग भूजल के स्रोतों से पूरी होती है। जाहिर है, तब न तो फसल उगाने के लिए पानी होगा और न उद्योग-धंधों के लिए। खेती-किसानी तो बर्बाद होगी ही, देश की बहुत बड़ी आबादी जल की एक-एक बूंद के लिए तरस सकती है।

विश्व में आज सबसे बड़ा संकट आतंकवाद और पर्यावरण हैं। लेकिन 2050 में जल त्रासदी सबसे बड़ा संकट होगा। भू-वैज्ञानिकों के अनुसार 2025 तक दुनिया की आबादी आठ अरब और 2050 तक नौ अरब को पार कर जाएगी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप आदि में बसने वाले देशों की बड़ी आबादी पानी की किल्लत से जूझ रही होगी। इन देशों में सब-सहारा, कांगो, मोजांबिक, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, चीन, कोरिया, घाना, केन्या, नामीबिया, अफगानिस्तान, अरब अमीरात, ईरान, इराक, सीरिया सहित कई देश शामिल होंगे। अभी अफ्रीकी और एशियाई देशों में पांच में से एक व्यक्ति पानी के लिए जूझ रहा है। 2050 में साढ़े पांच अरब लोग पानी के संकट से जूझ रहे होंगे। जिस तरह से विकासशील देशों में गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है, उससे यह अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक दुनिया की आधी आबादी शहरों में रह रही होगी। इससे जल संकट भीषण रूप ले सकता है।

संयुक्त राष्ट्र भी जल संकट को 2025 तक महासंकट में बदलते देख रहा है। इसलिए वह वर्षों पहले से दुनिया के देशों को जल संकट के प्रति सचेत करता रहा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना कम से कम पिच्यासी लीटर पानी मुहैया होना चाहिए। लेकिन तमाम कवायदों के बावजूद तीस फीसद लोगों को भी जरूरत भर पानी नहीं मिल पा रहा। इंटरनेशनल हाइड्रोलॉजिकल प्रोग्राम के अनुमान के मुताबिक वैश्विक तापमान (ग्लोबल वार्मिंग) के कारण अगले दस साल में वाष्पीकरण की रफ्तार आज की तुलना में दुगनी हो जाएगी। इसकी वजह से नदियों और अन्य जल स्रोतों का पानी कम हो जाएगा। गर्मी बढ़ने से ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघलेगी। इससे मीठा पानी खारे समुद्र में मिल जाएगा और मीठे पानी के जल-स्रोत सूखते चले जाएंगे। दूसरी समस्या जो सबसे विकराल रूप में सामने आ सकती है वह है, जल के लिए पलायन की। तब ऐसे स्थानों पर आबादी की भरमार हो सकती है जहां जल की उपलब्धता सुगम होगी। इससे आर्थिक-सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी।

केंद्रीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक देशभर में कुल सालाना बारिश 1170 मिलीमीटर होती है, और वह भी महज तीन महीने में। लेकिन इस अकूत पानी का इस्तेमाल हम महज बीस फीसद कर पाते हैं यानी अस्सी फीसद पानी हम बगैर इस्तेमाल किए बह जाने देते हैं। इसका खमियाजा हर साल पानी की बेहद कमी के रूप में भुगतते हैं। यदि बरसात के पानी को संरक्षित करने की योजना पर अमल करें तो पानी की किल्लत से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि पानी को लेकर होने वाली राजनीति से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा।

लेकिन बात इतनी-सी नहीं है। जिन इलाकों में बरसात बहुत कम होती है, वहां तो पाताल का पानी ही एकमात्र स्रोत होता है, वहां कैसे पानी की किल्लत से उबरा जाए, इस पर गौर करने की जरूरत है। देश के एक बड़े हिस्से में हर साल सामान्य से भी बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, बुंदेलखंड जैसे इलाकों में लोगों को बेहद सूखे की स्थिति से रूबरू होना पड़ रहा है। पानी की किल्लत के अलावा पेयजल का संकट भी देश के ज्यादातर प्रदेशों में है। राजधानी दिल्ली का पानी भी पीने के काबिल नहीं रह गया है। चंडीगढ़ स्थित लेबोरेटरी के परीक्षण के मुताबिक दिल्ली में जमीन के नीचे के पानी में क्लोराइड की मात्रा तय सीमा से बहुत अधिक एक हजार फीसद तक पाई गई थी। इसी तरह कैलशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, फेरिक (लोहा) और कैडमियम की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। इन तत्त्वों से युक्त पानी पीने से हृदयघात, किडनी पर बुरा असर, लीवर का संक्रमण, कैंसर, दांत संबंधित बीमारियां, तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर, त्वचा संबंधी रोग, तनाव, दमा जैसी अनेक समस्याएं बहुलता से देखी जा रही हैं।

निम्न जलस्तर वाले इलाकों में पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है। यह इससे भी साबित होता है कि पिछले दस सालों में इन इलाकों में दो करोड़ से ज्यादा कुएं खोदे जा चुके हैं। ये कुएं दो सौ मीटर से लेकर एक हजार मीटर तक की गहराई वाले हैं। इससे पता चलता है कि जलस्तर हर साल दो से लेकर छह फुट तक नीचे जा रहा है। ऐसे में बरसात के पानी को संरक्षित करके ही इस आसन्न संकट से उबरा जा सकता है। जल संकट को देखते हुए जल-सुरक्षा पर विचार करना बहुत जरूरी है। जल-दोहन करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर रोक लगनी चाहिए। कई राज्यों में व्यक्तिगत रूप से कुंआ खोदने और ट्यूबवेल लगाने पर रोक लगाई जा चुकी है। पाताल के पानी में जहरीले तत्त्वों की मात्रा का अधिक बढ़ना भी समस्या का बड़ा पहलू है। इस समस्या का कोई हल निकट समय में होता नहीं दिखाई पड़ रहा है।

भारत में पानी की किल्लत पिछले दस-पंद्रह सालों में ज्यादा बढ़ी है। इसका कारण सरकार की गलत नीतियां हैं। इन नीतियों का ही परिणाम रहा है कि राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में जल-स्तर दस से पंद्रह फीट तक नीचे चला गया है। इन इलाकों में बोतलबंद पानी का कारोबार बड़े पैमाने पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही कर रही हैं, शीतलपेय बनाने के विशालकाय कारखाने चल रहे हैं। जल माफिया पानी की चोरी करके रात-दिन पानी के संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। समस्याएं गंभीर हैं, इसलिए इन पर तुरंत गौर करने की जरूरत है।

महाकाय बजट

उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक के इतिहास में अपना सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बजट का आकार चार लाख उन्यासी हजार करोड़ रुपए है। यानी पिछले बजट से करीब बारह फीसद अधिक। इसमें बाईस हजार करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई हैं। बजट बड़ा हो, तो विकास की उम्मीदें भी बड़ी होती हैं। पर इस बजट में जिन क्षेत्रों के विकास और उनमें पैसे खर्च करने के प्रावधान को बढ़-चढ़ कर प्रदर्शित किया गया है, उससे तरक्की की आंशिक रूपरेखा ही सामने आ पाती है। इसमें धर्म और संस्कृति के विकास पर अधिक जोर है। तीर्थ स्थलों को विकसित करने के लिए दो सौ सात करोड़ रुपए का प्रावधान है। अयोध्या में हवाई अड्डा बनाने के लिए दो सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन, वाराणसी, श्रावस्ती, कुशीनगर आदि धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास के लिए अलग-अलग भारी-भरकम मद निर्धारित किए गए हैं। योगी सरकार का धर्म के प्रति झुकाव छिपी बात नहीं है, इसलिए धार्मिक स्थलों के विकास और वहां सुविधाएं मुहैया कराने पर उसका जोर स्वाभाविक है।

नई योजनाओं में सबसे अधिक गोवंश संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर जोर है। उसमें निराश्रित पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने, उनकी देखरेख आदि के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार अलग-अलग राशि तय की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं के रखरखाव और गोशाला निर्माण के लिए दो सौ सैंतालीस करोड़ साठ लाख रुपए का आबंटन किया गया है। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कान्हा गोशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना के लिए दो सौ करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। इसके साथ ही पंडित दीनदयाल लघु डेयरी योजना के संचालन के लिए चौंसठ करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसके तहत दस हजार इकाइयों की स्थापना प्रस्तावित है। पिछले करीब दो सालों में, जब से गोमांस और गोवंश की बिक्री पर प्रतिबंध लगा है, किसानों और पशुपालकों ने गायों के बछड़ों को बेचने के बजाय खुला छोड़ना शुरू कर दिया है। इससे मवेशियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। इसे लेकर किसानों में खासी नाराजगी है। ऐसे में योगी सरकार के लिए इस समस्या से पार पाना जरूरी था। ये योजनाएं उसी को ध्यान में रख कर तैयार की गई हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे किसानों को राहत मिलेगी और बेसहारा पशुओं को आश्रय मिल सकेगा।

योगी सरकार के बजट में आवास योजना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना और पेयजल योजना पर भी जोर दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के लिए छह हजार दो सौ चालीस करोड़ रुपए, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के लिए तीन हजार चार सौ अट्ठासी करोड़ रुपए और बुंदेलखंड के गांवों में पेयजल पाइपलाइन पर खर्च के लिए तीन हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए तीन हजार एक सौ चौरानबे करोड़ रुपए का प्रावधान है। इससे निस्संदेह निम्न आयवर्ग और पिछड़े इलाकों के लोगों की स्थिति में कुछ सुधार की उम्मीद बनती है। पर राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा की दशा भी दयनीय है। इसलिए इन क्षेत्रों में भी संतोषजनक बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी। रोजगार के नए अवसर पैदा करने वाली योजनाओं और परियोजनाओं का खाका तैयार करना भी जरूरी था। फिर उत्तर प्रदेश सरकार इतने बड़े बजट के लिए धन का प्रबंध कैसे करेगी, देखने की बात होगी।

कल्पमेधा

प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से हजार गुनी प्रभावशाली और स्थायी होती है।
-महात्मा गांधी

वसंत की अगवानी

प्रयाग शुक्ल

दुनिया मेरे आगे

मुझे फूल वाले परिसर बहुत पसंद हैं। फिर ये परिसर चाहे किसी मुहल्ले में घरों की कतार वाले हों या बहुमंजिले फ्लैटों वाले। बहुत बड़े आंगनों-बगीचियों वाले घरों में तो लाजिमी तौर पर पेड़-पौधे होते ही हैं और उनमें प्रायः एक बाउंड्री वाल भी होती है। पर हम यहां उन घरों की बात प्रमुख रूप से नहीं कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं उन घरों-फ्लैटों की बात जो अपेक्षाकृत छोटे हैं और जिनमें अपनी कोई छोटी-बड़ी बगीची होती नहीं है, जब तक कि वे ग्राउंड फ्लोर वाले ऐसे फ्लैट न हों, जिनके पिछवाड़े, फूल-पौधों के लिए कुछ जमीन होती है। बहरहाल, छोटे घरों और फ्लैटों में से चाहे छोटी-सी बगीची वाले घर हों या बहुमंजिले फ्लैट, फूल-पौधे प्रायः गमलों में ही उगाए जाते हैं। उन्हें किसी बालकनी, कोने या मुंडेर पर रखा जाता है और उन फूल-पौधों की चिंता भी की जाती है; पानी देने की, खाद की, दवाओं के छिड़काव आदि की ताकि फूल-पौधों में कीड़े न लगें। जाहिर है कि ये फूल-पौधे मनुष्य की उसी इच्छा का परिणाम हैं कि आसपास कुछ हरियाली हो, फूलों के रूप में कुछ रंग हों, और घर-फ्लैट की सौंदर्यबोधी भूख भी कुछ तो मिटे।

यह जानना-देखना सुखद है कि अब प्रायः सभी शहरों-महानगरों में कहीं-न-कहीं, किसी फुटपाथ पर भी, भांति-भांति के छोटे बड़े गमले बिकते हुए दिखाई देते हैं। किसी साइकिल पर, या ठेले पर, माली फूल-पौधों को बेचने के लिए, कहीं रोपने के लिए तत्पर दिखाई पड़ते हैं। उनके अपने कुछ बंधे हुए ग्राहक भी होते हैं। ऐसे पुष्प प्रेमी भी समाज में हैं ही, जो थोड़ी-सी जगह में भी बगिया बना लेते हैं, स्वयं जाकर किसी नर्सरी से फूल-पौधे लाते हैं, कई तो बाकायदा एक विशेषज्ञ की तरह की जानकारी भी रखते हैं, यही कि कौन-से फूल सर्दियों के हैं, कौन-से गर्मियों-वसंत के! वे उनके नाम-गुण आदि भी जानते हैं और उनके पास बाकायदा ऐसी पुस्तकें-पत्रिकाएं भी होती हैं जो फूल-पौधों-वनस्पतियों की जानकारी देने वाली होती हैं।

दिल्ली एनसीआर में भी एक सुखद बात यह लगती ही है कि न तो ऐसे लोगों की कमी है, न ऐसे प्रयत्नों की कि परिसर में घरों-फ्लैटों में तो फूल पौधे रहें ही, परिसर के छोटे-मोटे पार्क में भी रहें। नोएडा के जिस परिसर में मैं रहता हूं, वहां प्रसन्न करने वाले पेड़-फूल-पौधे हैं, और प्रायः सभी ने अपने-अपने फ्लैट में कुछ फूल-पौधे गमलों में रखे हैं, जो निगाह में आते हैं, या किसी के यहां जाने पर आपका 'स्वागत' करते हैं।

सोचता हूं, इस वृहद फूल-पौधों वाले संसार की बातें, हमारी चर्चा से प्रायः ओझल रहती हैं। इन फूल-पौधों की अनिवार्यता पर सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर जोर न दिया जाता हो, सो बात नहीं, पर हमने इनको लेकर, रिहायशी परिसरों में ऐसी औपचारिक-अनौपचारिक मंडलियां बनाई नहीं हैं, या बनाई भी हैं तो बहुत कम, जहां सामूहिक रूप से फूल-पौधों के 'उन्नयन' की बात सोची जाए, छुट्टियों में किशोर-किशोरियों को भी फूल-पौधों को उगाने की प्रक्रिया पर कुछ बताया जाए, कौन-सा फूल किस नाम से पुकारा जाता है, यह उन्हें मालूम हो, उन्हें ही क्यों बड़े-बुजुर्गों को भी बहुत-सी जानकारियां कहां होती हैं!

हमारे परिसर में एक कुमार साहब हैं, वे मालियों के साथ, किसी माली की तरह जुटे रहते हैं। कुछ उनके प्रयत्नों से भी यह संभव हुआ है कि हर फूल-पौधे के आगे, जो परिसर के प्रांगण में हैं- उसके मेन गेट पर, क्लब के गेट पर, लॉन पर, पार्क में- उन सबके नामों की तख्तियां लगी हैं, इससे स्वयं मुझे बहुत-सी जानकारियां हुई हैं। हमारे परिसर में ही, एक प्रकार साहब भी थे, वे परिचितों को, फूल-पौधे भी भेंट करते थे। सुबह उनके यहां मित्रों की एक छोटी-सी मंडली ही जुटती थी, चाय-चर्चा पर और अगर उस मंडली में सहसा कोई ऐसा परिचित-अपरिचित आ जाता था जो फूल-पौधों में विशेष दिलचस्पी दिखाता था, तो सब कुछ छोड़ कर वे उसी के साथ व्यस्त हो जाते थे। मराठी-मूल के थे। लखनऊ में रहे थे। अवकाश के बाद नोएडा आकर बसे थे। संगीत प्रेमी थे।

मैंने दो-एक बार जब किसी फूल-पौधे के बारे में जानकारी चाही तो, अगर उन्हें स्वयं वह मालूम न थी तो मिनटों में मुझे उपलब्ध कराई। हां, कितना बड़ा संसार है फूलों का, उनसे जुड़े शब्दों का, जिनका स्मरण मात्र मन को कुछ तो खिला ही देता है: 'धीरे से आना बगियन में...' का 'बगियन' हो, या क्यारी, फुलवारी या बाग-बगीची कुंज, पुष्प-लता, कलियां-पंखुड़ियां, तितलियां भ्रमर, कुसम-कानन!... भला कोई अंत है!

हम महानगर वासियों के आसपास अगर इन सबकी थोड़ी बहुत मौजूदगी न हो, इन सबकी थोड़ी-बहुत स्मृतियां, तो वह कितना नीरस लगने लगे। वसंत आ रहा है, उसकी अगवानी, भला हम फूलों के बिना कर सकते हैं, क्योंकि वह जितना अपने को धूप-हवा में व्यस्त करता है, उतना फूलों वनस्पतियों में भी।

दावे पर संशय

हम अक्सर सुनते आए हैं कि लोग जब हर तरफ से निराश हो जाते हैं तो बड़े भरोसे के साथ सीबीआइ जांच की मांग करते हैं और कहते हैं कि उसकी जांच में पूरी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआइ ने कई बार नामी चेहरों के खिलाफ सबूत लाकर उन्हें बेनकाब कर इसे साबित करके भी दिखाया है। सीबीआइ की बदौलत ही आज वे लोग जेल में सजा काट रहे हैं। लेकिन जिस तरह पश्चिम बंगाल में सीबीआइ अधिकारियों के साथ कोलकाता पुलिस पेश आई वह बेहद अफसोसनाक है। पुलिस के बर्ताव को देखकर ऐसा लगा जैसे वह किसी गंभीर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर चुकी हो! कायदे से तो वहां की पुलिस का फर्ज सीबीआइ आधिकारियों को सुरक्षा देने का था। पर हकीकत में हुआ इसके विपरीत। ममता बनर्जी का कहना था कि यह तख्तापलट की कोशिश है, अघोषित इमरजेंसी है! सीबीआइ के चालीस लोग जाकर भला कैसे तख्तापलट कर सकते हैं? क्या अब तक सीबीआइ ने जिन राज्यों में छापेमारी की वहां इमरजेंसी जैसे हालत बन गए?

सवाल यह भी है कि भारत जैसे देश में, जहां किसी न किसी राज्य में चुनावी माहौल बना रहता है, तो क्या आगे से सीबीआइ चुनाव के दिनों में अपनी जांच को रोक कर बैठ जाए? इस वाकये के बाद यकीनन सीबीआइ के आधिकारियों के मन में असुरक्षा की भावना बैठ जाएगी। वर्तमान समय में सीबीआइ कई बड़े मामलों की तहकीकात में जुटी है। आने वाले समय में वे लोग भी जांच से बचने के लिए कोई नया पाखंड रच सकते हैं। यदि सीबीआइ की कार्यशैली गलत थी तो ममता धरना देने की बजाय कोर्ट जाकर संवैधानिक जीत हासिल कर सकती थीं। उससे हर कोई उनकी तारीफ करता। सवाल यह भी है कि क्या ममता किसी गरीब के साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ भी सर्द रात में इतनी तत्परता दिखाने का कष्ट करेंगी?

चुनावों को लेकर तृणमूल कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच तनातनी को देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि सीबीआइ इस राजनीतिक विवाद में मोहरा बन गई। जैसे ही ममता धरने पर बैठीं कि देखते ही देखते धरनास्थल पर विपक्ष के कई नेता पहुंच गए। लेकिन फिर भी बड़े नेताओं ने वहां से दूरी बनाए रखी। शायद उन्हें ममता के पुलिस कमिश्नर के पाक-साफ होने पर यकीन नहीं था। इसके बाद अदालत ने भी पुलिस कमिश्नर को पूछताछ में सहयोग देने का आदेश देकर साफ कर दिया कि दाल में कुछ काला है। अदालत के आदेश से साफ है कि सीबीआइ बेवजह बंगाल नहीं पहुंची थी लेकिन फिर भी उसे बेइज्जत होना पड़ा। यदि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर सबूतों को नष्ट करने के दोषी पाए जाते हैं तो क्या ममता सार्वजनिक मंच पर सीबीआइ से माफी मांगेंगी? चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों की मर्यादा तो पहले से ही गिर चुकी है। लेकिन अपनी छवि चमकाने के लिए इस तरह से जांच एंजेंसियों को रोकना ठीक नहीं कहा जा सकता। सीबीआइ को रोक कर ममता विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व जरूर कर सकती हैं, लेकिन गठबंधन की दिशा जनता ही तय करेगी। सारदा घोटाले में सबसे ज्यादा बंगाल की जनता के पैसे ही डूबे हैं। ऐसे में ममता का आरोपी के साथ चट्टान की तरह आकर खड़े होना उनकी ईमानदार राजनीति के दावे पर भी संशय पैदा करता है।

● *रोहित यादव, महर्षि दयानंद विवि, रोहतक*

कुपोषण के विरुद्ध

भारत में कुपोषण से निपटने और खाद्य सुरक्षा को लेकर विभिन्न योजनाएं चलाई गईं लेकिन समस्या की विकरालता को देखते हुए वे नाकाफी तो थीं ही, प्रक्रियात्मक विसंगतियों और भ्रष्टाचार की वजह से तकरीबन बेअसर भी साबित हुई हैं। दरअसल, भूख से बचाव यानी खाद्य सुरक्षा के तहत सभी नागरिकों को जरूरी पोषक तत्त्वों से परिपूर्ण भोजन उनकी जरूरत के हिसाब से समय पर और गरिमामय तरीके से उपलब्ध करना किसी भी सरकार का पहला दायित्व है। लेकिन हमारे देश में भूख और कुपोषण की समस्या आज भी विकराल बनी हुई है। सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास तो बहुत किए है लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है। कुपोषण के कारण विकलांग बच्चे दिखने को मिलते हैं। सरकार को कुपोषण दूर करने के लिए तत्काल प्रभावी उपाय करने चाहिए।

● *मोहम्मद आसिफ, दिल्ली विश्वविद्यालय*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

अकेलेपन की कैद

हमारे देश में अकेलेपन से होने वाला तनाव दिन-ब-दिन तेजी से बढ़ रहा है। सभी को परिवार के साथ रहना पसंद है लेकिन आज युवक अपने करीयर के चक्कर में किसी को साथी बनाने से बचते दिख रहे हैं। अकेलेपन से पीड़ित लोगों में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की देखी जा रही है और यही आगे भविष्य में उनके अकेलेपन का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में व्यक्ति कामयाबी और अपना लक्ष्य तो हासिल कर लेता है, लेकिन उम्र भर बिना किसी साथी के ही रह जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे के 2004 के आकड़ों के मुताबिक देश में 12.3 लाख युवक और 36.8 लाख महिलाएं अकेलेपन की शिकार थीं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि ब्रिटेन में तो पिछले साल अकेलापन मंत्रालय बनाने की जरूरत आ पड़ी थी। व्यक्ति के लिए जितना जरूरी कामयाबी और लक्ष्य पाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी एक आत्मीय साथी का जीवन में होना है। अकेलेपन की बीमारी से ग्रस्त रोगी मानसिक तनाव के शिकार बन जाते हैं। इस कारण उन्हें छोटी-छोटी परेशानियां भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। वे जल्द ही गुस्सा करने लगते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि अपने करीयर के साथ-साथ जीवन साथी का भी सही समय पर चुनाव किया जाए ताकि भविष्य में उन्हें अकेलेपन की गंभीर बीमारी का सामना न करना पड़े।

● *निशांत रावत, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली*

समय पर साइकिल

बिहार में मुख्यमंत्री साइकिल योजना के तहत छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि योजना में काफी तब्दीली करने की जरूरत है। साइकिल की व्यवस्था सैद्धांतिक तौर पर इसलिए की जाती है कि बच्चे मैट्रिक तक आसानी से शिक्षा हासिल कर सकें। लेकिन व्यावहारिक रूप में होता यह है कि साइकिल मिलते-मिलते बच्चा नौवीं क्लास पास कर जाता है जिससे उसे योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए जब बच्चे आठवीं कक्षा में पास हों उसी समय साइकिल योजना के लिए उन्हें राशि मुहैया कराई जाए। इससे छात्र-छात्राओं की पढ़ाई नहीं छूटेगी। सरकारी व्यवस्था पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि राशि को सरकार देती ही है।

● *मिथिलेश कुमार, भागलपुर*